

रक्षा गलियारे में विकसित होगा एमएसएमई कॉरिडोर

200 करोड़ से 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा केंद्र, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा

संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। डिफेंस कॉरिडोर में एमएसएमई तकनीकी सेंटर के रूप में एक बड़ा गलियारा विकसित किया जाएगा। इस सेंटर पर जहां अत्याधुनिक मशीन से तकनीकी प्रस्तुत होगी, वहीं विशेषज्ञों की ओर से छोटे-छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए, 20 एकड़ यहां भूमि सुरक्षित कर ली गई है। इसके विकास के लिए 200 200 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

एमएसएमई कॉरिडोर के बनने से जहां छोटे कारोबारियों को यहां काम करने का मौका मिलेगा, वहीं सरकार से तमाम सुविधाएं मुहैया होंगी। गरौठा तहसील में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण एरच कस्बे से सटे छह गांवों की 1034 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है। कॉरिडोर में यूनिट की स्थापना के लिए 25 निवेशकों ने करार किया है। उनमें 14 को जमीन भी

बड़ी इकाइयां छोटे उद्यमियों की करेंगी मदद

बड़ी रक्षा इकाइयां उत्पादों के कलपुर्जे आदि के निर्माण में छोटी इकाइयों की मदद लेती है। एक बड़ी रक्षा इकाई कम से कम 100 इकाइयों को ऑर्डर देती है। कॉरिडोर में एमएसएमई इकाइयों को तैयार किया जाएगा। न केवल उन्हें अत्याधुनिक मशीनों से टेस्टिंग के गुण सिखाएं जाएंगे बल्कि उन्हें विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षित किया जाएगा। इनमें राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों का लाभ छोटे उद्यमियों को दिया सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टॉप ड्यूटी में छूट के साथ-साथ अन्य लाभ दिए जाएंगे।

इन रक्षा उपकरणों का होगा निर्माण

डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित की जा रही इकाइयों में रक्षा उपकरणों व उनसे जुड़ी सामग्री का निर्माण किया जाएगा। यहां राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल व अन्य छोटे हथियार व कलपुर्जे बनेंगे। इसके अलावा, गन पाउडर, गोला-बारूद, रक्षा उपकरणों के पार्ट्स, रक्षा वाहन, ड्रोन, रडार, विशेष कैमरे, छोटे-बड़े हथियार, गायरो चेंसिस, विमान अवरोधक जाल, मिसाइल-रॉकेट-लड़ाकू विमानों में उपयोग होने वाले पुर्जों का निर्माण, सीमा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न घटकों का निर्माण, विस्फोटक व तोपों का निर्माण।

आवंटित भी कर दी गई है। कंपनियां स्ट्रक्चर खड़ा करने में जुटी हुई हैं। इन्हीं यूनिटों में एक यूनिट तकनीकी सेंटर के रूप में विकसित की जाएगी।

एस-2 एरिया में करीब 20 एकड़ भूमि इसके लिए सुरक्षित कराई गई। इस पर 200 करोड़

रुपये खर्च होंगे।

उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी का कहना है कि डिफेंस कॉरिडोर में आने वाली कंपनियों से बुंदेलखंड की औद्योगिक तस्वीर में बड़ा बदलाव होगा। छोटे उद्यमियों को डिफेंस एमएसएमई के तौर पर नया प्लेटफॉर्म दिया जाएगा।